

श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन (SKPF) एवं WINCOMPETE- संयुक्त टेस्ट सीरीज - 2026

समय: 2:00 घण्टे |

| अधिकतम अंक: 300

विषय: संघीय सरकार और आयोग

टेस्ट संख्या: [15]

अभ्यर्थी का नाम: _____

अनुक्रमांक (Roll No.): _____

परीक्षा केंद्र _____

हस्ताक्षर अभ्यर्थी: _____

हस्ताक्षर वीक्षक: _____

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पुस्तिका में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प (A, B, C, D, E) दिए गए हैं।
2. प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक निर्धारित हैं।
3. **नकारात्मक अंकन (Negative Marking):** प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा।
4. OMR उत्तर पत्रक में पाँच विकल्प (A, B, C, D, E) में एक का अंकन करना है। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं, तो अनिवार्य रूप से विकल्प 'E' को अंकित करें।
5. यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न को हल नहीं करता है और विकल्प 'E' को भी अंकित नहीं करता है, तो उस प्रश्न के लिए भी 1/3 भाग (1 अंक) काटा जाएगा। (नवीनतम RPSC नियम)
6. कच्चे कार्य (Rough work) के लिए स्थान इस पुस्तिका के अंत में दिया गया है।
7. अपने रोल नम्बर और अन्य विवरण केवल निर्धारित स्थान पर ही लिखें।

[प्रश्न अनुभाग 1 से 20]

प्रश्न 1:

कथन I : राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, किंतु राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।

कथन II: राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

कथन III : महाभियोग प्रस्ताव के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।

उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन/कथन समूह सत्य है :

- A) केवल 1
- B) केवल 1 और 2
- C) केवल 2 और 3
- D) केवल 1 और 3

प्रश्न 2:

कथन: राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि संसद के पुनः समवेत होने की तिथि से छह सप्ताह होती है।

कारण: अध्यादेश निर्माण की शक्ति राष्ट्रपति की एक स्वविवेकिय शक्ति है जिसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है।

- A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है
- B) A और R दोनों सत्य हैं परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है
- C) A सत्य है, किन्तु R असत्य है
- D) A असत्य है, किन्तु R सत्य है

प्रश्न 3:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की शक्ति प्राप्त है, जिसमें सेना अदालत द्वारा दिए गए दंड भी शामिल हैं।

निष्कर्ष I : राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से अधिक विस्तृत है

क्योंकि इसमें मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल के दंड दोनों की माफी शामिल है।

निष्कर्ष II : राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करते समय अपने स्वविवेक का उपयोग कर सकता है और मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है।

उपरोक्त में से कौन सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं?

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
- B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
- C) निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं
- D) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं

प्रश्न 4:

सूची I (अनुच्छेद/प्रावधान):

- a) अनुच्छेद 75(1)
- b) अनुच्छेद 78
- c) अनुच्छेद 74(1)
- d) अनुच्छेद 75(3)

सूची II (विवरण):

- I. मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देना
- II. मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व
- III. प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रियों की नियुक्ति
- IV. राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य

सही कूट का चयन करें:

- A) a-I, b-II, c-III, d-IV
- B) a-III, b-IV, c-I, d-II
- C) a-IV, b-III, c-II, d-I
- D) a-II, b-I, c-IV, d-III

प्रश्न 5:

A) 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

B) किसी भी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से कम नहीं होगी, लेकिन यह संख्या 12 से कम नहीं होगी।

C) केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की तीन श्रेणियां होती हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री।
D) सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत लोकसभा में किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है।

प्रश्न 6:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह संघ के प्रशासन और विधायी प्रस्तावों से संबंधित सभी जानकारी राष्ट्रपति को दे। यदि राष्ट्रपति ऐसी कोई सूचना मांगें, तो प्रधानमंत्री उसे उपलब्ध कराने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हैं।

उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सर्वाधिक उपयुक्त है?

- A) प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रति प्रशासनिक रूप से पूर्णतः उत्तरदायी हैं तथा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के निर्णयों को अस्वीकार कर सकते हैं।
- B) प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को केवल उन्हीं सूचनाओं को देने के लिए बाध्य हैं जो मंत्रिमंडल की अनुमति से दी जाएं।
- C) प्रधानमंत्री की यह बाध्यता एक वैधानिक कड़ी है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को कार्यपालिका की वास्तविक गतिविधियों की जानकारी मिलती है।
- D) राष्ट्रपति स्वविवेक से किसी भी मंत्री को सीधे बर्खास्त कर सकते हैं यदि प्रधानमंत्री सूचना न दें।

प्रश्न 7:

राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है?

- A) सभी मतदाताओं के वोटों का मूल्य समान होता है चाहे वे संसद के हों या विधानसभा के।
- B) विजेता उम्मीदवार को कुल डाले गए वैध मतों का साधारण बहुमत प्राप्त करना अनिवार्य होता है।
- C) मतदाता उम्मीदवारों की सूची में अपनी पसंद के अनुसार वरीयता दर्ज करता है।
- D) राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का मूल्य सभी राज्यों में सर्वदा एक समान रहता है।

प्रश्न 8:

कथन I : राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की शक्ति और प्रभाव वही होता है जो संसद के किसी अधिनियम का होता है।

कथन II : अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बनाने की शक्ति रखती है।

कथन III : राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी अपनी इच्छा से वापस ले सकता है, इसके लिए मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक नहीं है।

उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन/कथन समूह सत्य है :

- A) केवल 1 और 2
- B) केवल 2 और 3
- C) केवल 1 और 3
- D) 1, 2 और 3

प्रश्न 9:

कथन: भारतीय राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह द्वारा 1986 में डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में किया गया था।

कारण: संविधान में राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक पर अपनी सहमति देने या रोकने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

- A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है
- B) A और R दोनों सत्य हैं परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है
- C) A सत्य है, किन्तु R असत्य है
- D) A असत्य है, किन्तु R सत्य है

प्रश्न 10:

प्रधानमंत्री को राष्ट्र का मुख्य प्रवक्ता और सरकार का प्रमुख माना जाता है, जो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एकमात्र संवाद सेतु के रूप में कार्य करता है।

निष्कर्ष I : यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद स्वतः विघटित हो जाती है।

निष्कर्ष II : राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी भी अन्य मंत्री को प्रधानमंत्री की सहमति के बिना सीधे बर्खास्त कर सकता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं?

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
- B) केवल निष्कर्ष II सत्य है

- C) निष्कर्ष । और ॥ दोनों सत्य हैं
D) निष्कर्ष । और ॥ दोनों असत्य हैं

प्रश्न 11:

सूची I (मंत्रियों की श्रेणी):

- a) कैबिनेट मंत्री
b) राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
c) राज्य मंत्री
d) उपमंत्री

सूची II (विशेषता/कार्य):

- I. अपने विभाग का स्वतंत्र रूप से प्रभार संभालते हैं और कैबिनेट बैठकों में आमंत्रित किए जाने पर भाग लेते हैं
II. महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं और नीति निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं
III. नीति निर्माण में सीधे भाग नहीं लेते बल्कि प्रशासनिक और संसदीय कार्यों में सहायता करते हैं
IV. कैबिनेट मंत्रियों के अधीन कार्य करते हैं और विभागीय मामलों में उनकी सहायता करते हैं

सही कूट का चयन करें:

- A) a-I, b-II, c-III, d-IV
B) a-II, b-I, c-IV, d-III
C) a-III, b-IV, c-I, d-II
D) a-IV, b-III, c-II, d-I

प्रश्न 12:

- A) राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के आरोप पर महाभियोग चलाया जा सकता है, जिसकी शुरुआत संसद के किसी भी सदन से हो सकती है।
B) महाभियोग प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रस्तावित किया जाना चाहिए।
C) प्रस्ताव को पारित करने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम तीन-चौथाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
D) राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, किंतु राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं।

प्रश्न 13:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर संपूर्ण देश में या उसके किसी हिस्से में मंत्रिपरिषद् के लिखित अनुरोध पर राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जा सकता है।

इस अनुच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है?

- A) मूल संविधान में 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द का ही प्रयोग किया गया था।
B) राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित परामर्श आवश्यक है।
C) राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती।
D) आपातकाल की घोषणा के बाद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

प्रश्न 14:

- जब संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास उसकी अनुमति के लिए भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति के पास निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करने का क्या अर्थ होता है?
A) राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास अनिश्चित काल के लिए सुरक्षित रख सकता है।
B) राष्ट्रपति विधेयक को बिना किसी संशोधन के पुनः विचार के लिए संसद के पास लौटा सकता है।
C) राष्ट्रपति विधेयक को पूर्णतः अस्वीकृत कर सकता है और संसद उस पर दोबारा विचार नहीं कर सकती।
D) राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग केवल धन विधेयकों के संदर्भ में कर सकता है।

प्रश्न 15:

कथन I : राष्ट्रपति शासन की घोषणा के दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा उसका अनुमोदन होना अनिवार्य है।

कथन II: वित्तीय आपातकाल की घोषणा को संसद के अनुमोदन के बिना अनिश्चित काल तक जारी रखा जा सकता है।

कथन III : राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन/कथन समूह सत्य है :

- A) केवल 1 और 2
B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 3
D) केवल 1, 2 और 3

प्रश्न 16:

कारण: प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद् का प्राण होता है, यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दें तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद् का अस्तित्व समाप्त हो जाता है।

कारण: प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है।

- A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है
- B) A और R दोनों सत्य हैं परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है
- C) A सत्य है, किन्तु R असत्य है
- D) A असत्य है, किन्तु R सत्य है

प्रश्न 17:

91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से केंद्र और राज्यों दोनों में मंत्रिपरिषद् के आकार को सीमित किया गया है, जिसके तहत दलबदल के आधार पर मंत्रियों की नियुक्ति पर रोक लगाई गई है।

निष्कर्ष I : इस संशोधन के पश्चात दलबदल करने वाला संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य किसी भी मंत्री पद के लिए तब तक अपात्र रहेगा जब तक वह पुनः निर्वाचित न हो जाए।

निष्कर्ष II : इस संशोधन के अनुसार छोटे राज्यों में भी मंत्रिपरिषद् में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कम से कम पंद्रह अनिवार्य की गई है।

उपरोक्त में से कौन सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं?

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
- B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
- C) निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं
- D) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं

प्रश्न 18:

सूची I (क्षमादान के प्रकार):

- a) क्षमा
- b) प्रविलंबन
- c) परिहार
- d) विराम

सूची II (अर्थ/परिभाषा):

I. किसी दंड को कुछ समय के लिए टालना

II. दंड की प्रकृति को बदले बिना अवधि कम करना

III. विशेष परिस्थितियों में मूल दंड से कम सजा देना

IV. दोषी को दंड व सजा से पूर्णतः मुक्त करना

सही कूट का चयन करें:

- A) a-I, b-II, c-III, d-IV
- B) a-IV, b-I, c-II, d-III
- C) a-II, b-III, c-IV, d-I
- D) a-III, b-IV, c-I, d-II

प्रश्न 19:

A) भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है और संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां उसमें निहित होती हैं।

B) राष्ट्रपति महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है।

C) राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका अधिकारों का प्रयोग स्वयं सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार करता है।

D) राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर प्रधानमंत्री को उसके पद से कभी भी स्वेच्छा से हटा सकता है, भले ही लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त हो।

प्रश्न 20:

अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति देता है। यह शक्ति तभी प्रयोग की जा सकती है जब संसद के दोनों सत्रों में न हों। यह कानून संसद के पुनः समवेत होने पर छह सप्ताह के भीतर अनुमोदित होना अनिवार्य है।

इस पैराग्राफ और संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में कौन सा कथन तार्किक रूप से सर्वाधिक सही है?

A) अध्यादेश निर्माण की राष्ट्रपति की शक्ति उसकी एक अत्यंत व्यापक और असीमित विधायी शक्ति है जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती।

B) अध्यादेश की अधिकतम संभव आयु लगभग 6 महीने और 6 सप्ताह हो सकती है यदि संसद की बैठकें आहूत न की जाएं।

C) राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह के बिना भी अपनी इच्छा से किसी भी समय अध्यादेश जारी कर सकता है।

D) अध्यादेश केवल वित्तीय मामलों पर ही जारी किया जा सकता है, नीतिगत मामलों पर नहीं।

[प्रश्न अनुभाग 21 से 40]

प्रश्न 21:

कथन I : मंत्रिमंडलीय समितियां पूरी तरह से संविधानेतर (Extra-Constitutional) निकाय हैं, जिनका उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है।

कथन II: प्रधानमंत्री इन सभी मंत्रिमंडलीय समितियों के अनिवार्य रूप से अध्यक्ष होते हैं, चाहे वह राजनीतिक मामलों की समिति हो या नियुक्ति समिति।

कथन III : कैबिनेट सचिवालय सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के चार्ज के अधीन होता है और इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है।

उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन/कथन समूह सत्य है :

- A) केवल 1
- B) केवल 1 और 3
- C) केवल 2 और 3
- D) केवल 2

प्रश्न 22:

कथन: 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की कुल संख्या और उनके क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

कारण: यह प्रतिबंध देश के सभी राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रमों को समान रूप से प्रोत्साहित करने और जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय असंतुलन को रोकने के लिए लगाया गया था।

- A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है
- B) A और R दोनों सत्य हैं परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है
- C) A सत्य है, किन्तु R असत्य है
- D) A असत्य है, किन्तु R सत्य है

प्रश्न 23:

संसद के किसी सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करने के लिए सभापति तालिका (Panel of Chairpersons) के सदस्यों को नामित किया जाता है।

निष्कर्ष I : सभापति तालिका का कोई भी सदस्य उस समय स्थायी अध्यक्ष की भांति कार्य कर सकता है जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए।

निष्कर्ष II : सभापति तालिका के सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही नामित किया जाता है और वे सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं?

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
- B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
- C) निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं
- D) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं

प्रश्न 24:

सूची I (संसदीय शब्दावली):

- a) प्रश्नकाल
- b) शून्यकाल
- c) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
- d) कार्यस्थगन प्रस्ताव

सूची II (समय/अवधि/विशेषता):

- I. संसद की बैठक का पहला घंटा जिस दौरान मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं
- II. प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय जब बिना पूर्व सूचना के अत्यंत महत्वपूर्ण मामले उठाए जाते हैं
- III. किसी सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करना
- IV. देश में घटित किसी गंभीर तात्कालिक सार्वजनिक महत्व के मामले पर सदन की सामान्य कार्यवाही रोकना

सही कूट का चयन करें:

- A) a-I, b-II, c-III, d-IV
- B) a-IV, b-III, c-II, d-I
- C) a-III, b-I, c-IV, d-II
- D) a-II, b-IV, c-I, d-III

प्रश्न 25:

- A) धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं।
- B) धन विधेयक को पुनर्स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।
- C) राज्यसभा किसी धन विधेयक में संशोधन कर सकती है या उसे अधिकतम 30 दिनों के लिए अपने पास रोक सकती है।

D) यदि किसी विधेयक के धन विधेयक होने पर विवाद होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।

प्रश्न 26:

कैबिनेट सचिवालय भारत सरकार के नियमों के तहत कार्य करता है और यह मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने का मुख्य अभिकरण है। यह प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है और प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव इसका प्रशासनिक और राजनीतिक सलाहकार होता है।

उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में, कैबिनेट सचिव की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक तार्किक है?

- A) कैबिनेट सचिव देश का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है।
- B) कैबिनेट सचिव केवल गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा मामलों पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है।
- C) कैबिनेट सचिव का चयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और वह सीधे संसद के प्रति जवाबदेह होता है।
- D) कैबिनेट सचिव नीति निर्माण के दौरान विपक्ष के नेताओं को गोपनीय दस्तावेजों की जानकारी देने के लिए बाध्य है।

प्रश्न 27:

राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है?

- A) राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता है।
- B) राज्यसभा के एक-तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
- C) राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
- D) उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।

प्रश्न 28:

कथन I : लोकसभा अध्यक्ष के पास यह शक्ति होती है कि वह किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करे और उसका निर्णय अंतिम होता है।

कथन II: लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ लोकसभा के सदस्य के रूप में ही ग्रहण करता है, अलग से अध्यक्ष पद की कोई शपथ नहीं होती।

कथन III : दल-बदल के आधार पर लोकसभा सदस्यों की अयोग्यता का प्रश्न उठने पर उसका अंतिम निर्णय राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की सलाह पर लिया जाता है।

उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन/कथन समूह सत्य है :

- A) केवल 1 और 2
- B) केवल 2 और 3
- C) केवल 1 और 3
- D) केवल 1

प्रश्न 29:

कथन: संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो।

कारण: संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत केवल साधारण विधेयकों और वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में लागू होता है, धन विधेयकों या संविधान संशोधन विधेयकों पर नहीं।

- A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है
- B) A और R दोनों सत्य हैं परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है
- C) A सत्य है, किन्तु R असत्य है
- D) A असत्य है, किन्तु R सत्य है

प्रश्न 30:

संसद के सत्र आहूत करने और सत्रावसान की संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यपालिका और विधायिका का परस्पर संबंध निहित होता है।

निष्कर्ष I : राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन करने के बाद संसद में लंबित सभी विधेयक स्वतः समाप्त हो जाते हैं, चाहे वे किसी भी सदन में क्यों न हों।

निष्कर्ष II : सत्रावसान होने पर संसद में लंबित विधेयक या प्रस्ताव समाप्त नहीं होते हैं और वे आगामी सत्र में भी विचारणीय रहते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं?

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
- B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
- C) निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं
- D) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं

प्रश्न 31:

सूची I (संसदीय समितियां/भूमिका):

- a) राजनीतिक मामलों की समिति
- b) नियुक्ति समिति
- c) आर्थिक मामलों की समिति
- d) संसदीय कार्य समिति

सूची II (प्रमुख कार्य):

- I. देश की आर्थिक और वित्तीय नीतियों का समन्वय एवं अवलोकन करना
- II. केंद्र सरकार के उच्च पदों पर नियुक्तियों के मामलों पर निर्णय लेना
- III. देश की आंतरिक और बाह्य नीति से जुड़े महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों का निपटारा करना
- IV. संसद में सरकार के विधायी कार्यों और सत्र के कार्यक्रमों का सुचारू प्रबंधन करना

सही कूट का चयन करें:

- A) a-I, b-II, c-III, d-IV
- B) a-III, b-II, c-I, d-IV
- C) a-IV, b-III, c-II, d-I
- D) a-II, b-I, c-IV, d-III

प्रश्न 32:

- A) 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।
- B) संसद के प्रत्येक सदन की बैठक के लिए कोरम (गणपूर्ति) सदन के कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा होता है।
- C) लोकसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है जिसे 84वें संशोधन द्वारा सुरक्षित किया गया है।
- D) राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से राज्य के मतदाताओं द्वारा किया जाता है।

प्रश्न 33:

भारतीय संसद की विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत किसी साधारण विधेयक को कानून बनाने के लिए दोनों सदनों से पारित होना अनिवार्य है। यदि किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होता है, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है।

इस विधायी प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?

- A) साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में पुनः स्थापित किया जा सकता है।
- B) संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
- C) धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को संयुक्त बैठक बुलाने की मांग करने का पूर्ण अधिकार है।
- D) लोकसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक जब राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा उसे अधिकतम छह महीने के लिए रोक सकती है।

प्रश्न 34:

जब लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो उसे स्वीकार करने के लिए सदन में कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है?

- A) सदन की कुल संख्या का एक-तिहाई सदस्य
- B) कम से कम 50 सदस्य
- C) सदन की कुल संख्या का आधा बहुमत
- D) कम से कम 100 सदस्य

प्रश्न 35:

कथन I : वित्त विधेयक (श्रेणी I) को लोकसभा में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होती है, जबकि राज्यसभा इसे संशोधित या अस्वीकार कर सकती है।

कथन II: अनुच्छेद 110 में दी गई परिभाषा के अनुसार प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, किंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता।

कथन III : राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन करने की अनुशंसा कर सकती है, जिसे मानना लोकसभा के लिए संवैधानिक रूप से बाध्यकारी है।

उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन/कथन समूह सत्य है :

- A) केवल 1 और 2
- B) केवल 2 और 3

- C) केवल 1 और 3
D) केवल 3

प्रश्न 36:

कारण: लोकसभा अध्यक्ष सदन का पीठासीन अधिकारी होता है और उसे यह शक्ति प्राप्त है कि वह सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमों की व्याख्या करे।

कारण: लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही बहुमत से किया जाता है।

- A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है
B) A और R दोनों सत्य हैं परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है
C) A सत्य है, किन्तु R असत्य है
D) A असत्य है, किन्तु R सत्य है

प्रश्न 37:

संसद के सत्रों के संचालन और विधायी प्रक्रिया में कोरम (गणपूर्ति) का नियम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसके बिना सदन की कोई बैठक नहीं हो सकती।

निष्कर्ष I : यदि सदन की बैठक के दौरान गणपूर्ति पूरी नहीं है, तो पीठासीन अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह सदन को स्थगित कर दे या घंटी बजाकर कोरम पूरा करे।

निष्कर्ष II : गणपूर्ति के लिए लोकसभा में न्यूनतम 55 सदस्य और राज्यसभा में न्यूनतम 25 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है।

उपरोक्त में से कौन सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं?

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
C) निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं
D) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं

प्रश्न 38:

सूची I (संसदीय प्रक्रिया/पद):

- a) स्थगन प्रस्ताव
b) अविश्वास प्रस्ताव
c) विशेषाधिकार प्रस्ताव
d) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सूची II (संबंधित उद्देश्य):

- I. किसी मंत्री द्वारा सदन में तथ्यों को छिपाने या गलत जानकारी देने पर लाया जाना
II. लोक महत्व के किसी तत्काल गंभीर मामले पर बहस के लिए सदन की सामान्य कार्यवाही रोकना
III. सरकार के विरुद्ध बहुमत परीक्षण हेतु लोकसभा में लाया जाना
IV. किसी सार्वजनिक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करना

सही कूट का चयन करें:

- A) a-II, b-III, c-I, d-IV
B) a-I, b-II, c-III, d-IV
C) a-IV, b-I, c-II, d-III
D) a-III, b-IV, c-I, d-II

प्रश्न 39:

A) शून्यकाल (Zero Hour) भारतीय संसदीय प्रक्रिया की एक अनूठी देन है जो वर्ष 1962 से अस्तित्व में आई है।

B) लोकसभा का उपाध्यक्ष सदन का सदस्य न होने पर भी अपने पद पर बना रह सकता है यदि उसका कार्यकाल समाप्त हो जाए।

C) राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही किया जाता है।

D) संसद की बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल छह महीने से अधिक नहीं होना चाहिए।

प्रश्न 40:

भारत में बजट पारित होने की विधायी प्रक्रिया के विभिन्न चरण होते हैं, जिसमें अनुदान की मांगें, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक शामिल हैं। विनियोग विधेयक सरकार को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार देता है।

इस वित्तीय प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से सर्वाधिक उपयुक्त है?

- A) विनियोग विधेयक पारित किए बिना सरकार संचित निधि से एक भी रुपया व्यय कर सकती है।
B) अनुदान की मांगों पर मतदान केवल लोकसभा में होता है, राज्यसभा में इन पर मतदान का अधिकार नहीं है।
C) वित्त विधेयक को संसद के किसी भी सदन में राज्यसभा द्वारा पहले प्रस्तुत किया जा सकता है।

D) बजट पारित होने की प्रक्रिया में राज्यसभा की वित्तीय मामलों में लोकसभा से अधिक शक्तियां होती हैं।

[प्रश्न अनुभाग 41 से 60]

प्रश्न 41:

कथन I : लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं जिनमें 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से होते हैं।

कथन II: इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है और परंपरा के अनुसार इस समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल का ही सदस्य होता है।

कथन III : प्राक्कलन समिति देश की सबसे बड़ी संसदीय समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं और इसके सभी सदस्य केवल राज्यसभा से चुने जाते हैं।

उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन/कथन समूह सत्य है :

- A) केवल 1
- B) केवल 1 और 2
- C) केवल 2 और 3
- D) केवल 1 और 3

प्रश्न 42:

कथन: संसद सदस्यों को मिलने वाले संसदीय विशेषाधिकार केवल सदन की बैठक के दौरान ही लागू होते हैं, सत्र के सत्रावसान या विघटन के समय इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है।

कारण: अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद के प्रत्येक सदन को अपने सदस्यों के विशेषाधिकारों के उल्लंघन या सदन की अवमानना पर दंडित करने की पूर्ण और अनन्य शक्ति प्राप्त है।

- A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है
- B) A और R दोनों सत्य हैं परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है
- C) A सत्य है, किन्तु R असत्य है
- D) A असत्य है, किन्तु R सत्य है

प्रश्न 43:

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वर्तमान में कॉलेजियम प्रणाली प्रचलित है

जिसमें मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठतम न्यायाधीशों का निकाय नाम तय करता है।

निष्कर्ष I : राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था।

निष्कर्ष II : कॉलेजियम प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख भारतीय संविधान के मूल अनुच्छेद 124 में किया गया था जिसे बाद में संशोधित किया गया।

उपरोक्त में से कौन सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं?

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
- B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
- C) निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं
- D) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं

प्रश्न 44:

सूची I (संविधान के अनुच्छेद):

- a) अनुच्छेद 131
- b) अनुच्छेद 136
- c) अनुच्छेद 143
- d) अनुच्छेद 124

सूची II (न्यायालय का क्षेत्राधिकार/प्रावधान):

- I. उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन
- II. उच्चतम न्यायालय का मूल एवं आरंभिक क्षेत्राधिकार
- III. राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगने की शक्ति
- IV. अपील के लिए विशेष अनुमति याचिका की शक्ति

सही कूट का चयन करें:

- A) a-II, b-IV, c-III, d-I
- B) a-I, b-III, c-II, d-IV
- C) a-IV, b-I, c-II, d-III
- D) a-III, b-II, c-IV, d-I

प्रश्न 45:

A) लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के प्रतिवेदन की जांच करती है और सीएजी को इस समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है।

B) सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी कुल 22 सदस्य होते हैं जिनमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं।

C) प्राक्कलन समिति का मुख्य कार्य बजट अनुमानों की जांच करना और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव देना है, और इसके अध्यक्ष का संबंध विपक्षी दल से होना अनिवार्य है।
D) दल-बदल विरोधी कानून (10वीं अनुसूची) के तहत अयोग्यता संबंधी विवाद पर अंतिम निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा लिया जाता है।

प्रश्न 46:

भारतीय संविधान की पांचवीं और नौवीं अनुसूची के विपरीत, 10वीं अनुसूची को 52वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो राजनीतिक दल-बदल को रोकने के लिए कड़े प्रावधान करती है। इसके तहत स्वेच्छा से दल छोड़ने या व्हिप का उल्लंघन करने पर सांसद या विधायक की सदस्यता समाप्त हो सकती है, सिवाय उस स्थिति के जब दल का किसी अन्य दल में एक-तिहाई विलय हो जाए।

उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में दल-बदल कानून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से सर्वाधिक उपयुक्त है?

- A) दल-बदल कानून के तहत विलय के लिए अब मूल दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों की सहमति आवश्यक है, जिसे 91वें संशोधन द्वारा बदला गया था।
B) दल-बदल संबंधी मामलों की न्यायिक समीक्षा किसी भी परिस्थिति में न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है।
C) पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम होता है और इस पर कभी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।
D) यह कानून केवल संसद सदस्यों पर लागू होता है, राज्य विधानमंडलों के सदस्यों पर नहीं।

प्रश्न 47:

संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जो इसके मूल क्षेत्राधिकार का हिस्सा है।

- A) उच्चतम न्यायालय केवल सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध ही रिट जारी कर सकता है, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं।
B) संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता क्षेत्र को अन्य न्यायालयों को भी प्रदान कर सकती है, बिना उच्चतम न्यायालय की शक्ति छीने।

C) अनुच्छेद 32 के तहत उपचार का अधिकार स्वयं एक मूल अधिकार है जिसे आपातकाल के दौरान भी पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है।
D) उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त नहीं है।

प्रश्न 48:

कथन I : जनहित याचिका (PIL) की अवधारणा भारत में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और वी.आर. कृष्ण अय्यर द्वारा शुरू की गई थी।

कथन II: जनहित याचिका दायर करने के लिए पीड़ित व्यक्ति का स्वयं न्यायालय में उपस्थित होना अनिवार्य होता है, कोई अन्य व्यक्ति या संस्था उसकी ओर से याचिका नहीं ला सकती।

कथन III : न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) कार्यपालिका और विधायिका द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहने पर न्यायपालिका के हस्तक्षेप को दर्शाती है।

उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन/कथन समूह सत्य है :

- A) केवल 1 और 2
B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 3
D) केवल 1

प्रश्न 49:

कथन: उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 143) राष्ट्रपति को किसी भी सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामले पर न्यायालय की राय लेने का अधिकार देता है, और न्यायालय इस पर अपनी राय देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है।

कारण: उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दी गई सलाह राष्ट्रपति पर किसी भी स्थिति में बाध्यकारी नहीं होती है, और न ही यह पूर्व दृष्टांत के रूप में पूर्ण रूप से लागू होती है।

- A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है
B) A और R दोनों सत्य हैं परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है
C) A सत्य है, किन्तु R असत्य है
D) A असत्य है, किन्तु R सत्य है

प्रश्न 50:

केशवानंद भारती वाद (1973) ने भारतीय संविधान के इतिहास में आधारभूत संरचना (Basic Structure) के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसने संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर सीमाएं तय कीं।

निष्कर्ष I : इस सिद्धांत के अनुसार संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, बशर्ते वह संविधान के मूल ढांचे या बुनियादी विशेषताओं को नष्ट न करे।

निष्कर्ष II : न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) की शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय के पास है, देश के उच्च न्यायालयों के पास यह शक्ति नहीं है।

उपरोक्त में से कौन सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं?

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
- B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
- C) निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं
- D) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं

प्रश्न 51:

सूची I (वाद/मामला):

- a) केशवानंद भारती वाद
- b) मिनर्वा मिल्स वाद
- c) गोलकनाथ वाद
- d) एल. चंद्रकुमार वाद

सूची II (संवैधानिक विषय):

- I. मूल अधिकारों में संशोधन से संबंधित संसद की शक्ति पर रोक
- II. संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत
- III. न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान की मूल विशेषता है
- IV. संसद की संशोधन शक्ति और न्यायिक समीक्षा में संतुलन

सही कूट का चयन करें:

- A) a-II, b-IV, c-I, d-III
- B) a-I, b-II, c-III, d-IV
- C) a-IV, b-III, c-II, d-I
- D) a-III, b-I, c-IV, d-II

प्रश्न 52:

A) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा

अलग-अलग विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना आवश्यक होता है।

B) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है।

C) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए सौंपते हैं।

D) न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 के तहत महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं।

प्रश्न 53:

संसदीय विशेषाधिकारों के अंतर्गत संसद सदस्यों को सदन के भीतर और बाहर कुछ विशेष उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं, ताकि वे अपने दायित्वों का निर्भय होकर पालन कर सकें।

इस विषय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?

- A) सदस्यों को संसद के भीतर कही गई किसी भी बात या दिए गए मत के लिए किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।
- B) संसद के सत्र के दौरान और उसके आरंभ होने से 40 दिन पहले तथा समाप्त होने के 40 दिन बाद तक सदस्यों को दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
- C) यह उन्मुक्ति आपराधिक मामलों और निवारक नजरबंदी (Preventive Detention) के मामलों में भी सदस्यों को पूर्ण रूप से बचाती है।
- D) सदन के प्रकाशनों के अधिकार के तहत संसद द्वारा प्रकाशित रिपोर्टें या कार्यवाहियों के प्रकाशन पर मानहानि का मुकदमा नहीं चल सकता।

प्रश्न 54:

उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति याचिका (SLP - अनुच्छेद 136) की शक्ति एक विशिष्ट और असाधारण शक्ति है।

जब कोई पक्षकार एसएलपी (SLP) के तहत अपील करता है, तो उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है?

A) उच्चतम न्यायालय देश के किसी भी न्यायालय या अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति से अपील की अनुमति देने के लिए विवेकशील रूप से सक्षम है।

- B) यह अधिकार नागरिकों का एक मौलिक और वाद योग्य अधिकार है जिसे न्यायालय अस्वीकार नहीं कर सकता।
C) इस शक्ति का प्रयोग केवल उच्च न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध ही किया जा सकता है, निचली अदालतों के विरुद्ध नहीं।
D) इसके तहत केवल दीवानी मामलों की ही सुनवाई की जा सकती है, आपराधिक मामलों की नहीं।

प्रश्न 55:

कथन I : सार्वजनिक उपक्रम समिति (CoPU) संसद की वित्तीय समितियों में से एक है जिसका मुख्य कार्य सरकारी कंपनियों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच करना है।

कथन II: इस समिति के सभी सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, और राज्यसभा का इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है।

कथन III : उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार मुख्य रूप से संवैधानिक, दीवानी और आपराधिक मामलों की अपीलों से संबंधित होता है।

उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन/कथन समूह सत्य है :

- A) केवल 1 और 2
B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 3
D) केवल 1

प्रश्न 56:

कारण: दलबदल विरोधी कानून के तहत पीठासीन अधिकारी के निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने किहोटो होलोहन वाद में इसे वैध माना था।

कारण: दल-बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रश्न केवल निर्वाचित सदस्यों पर लागू होता है, मनोनीत सदस्यों पर नहीं।

- A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है
B) A और R दोनों सत्य हैं परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है
C) A सत्य है, किन्तु R असत्य है
D) A असत्य है, किन्तु R सत्य है

प्रश्न 57:

संसदीय समितियों का तंत्र संसद को कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण रखने और वित्तीय मामलों की गहरी छानबीन करने में सहायता करता है।

निष्कर्ष I : प्राक्कलन समिति नीतिगत मामलों पर सीधे तौर पर टिप्पणी नहीं करती, बल्कि यह सुझाव देती है कि नीतियां कितनी किफायती और प्रशासनिक रूप से कुशल हैं।

निष्कर्ष II : लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति सत्ताधारी दल के किसी वरिष्ठ सांसद में से की जाती है ताकि सरकार के वित्तीय कार्यों में सहयोग मिल सके।

उपरोक्त में से कौन सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं?

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
C) निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं
D) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं

प्रश्न 58:

सूची I (न्यायालय का क्षेत्राधिकार):

- a) मूल क्षेत्राधिकार
b) अपीलीय क्षेत्राधिकार
c) परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार
d) रिट क्षेत्राधिकार

सूची II (संवैधानिक अनुच्छेद):

- I. अनुच्छेद 132 और 133
II. अनुच्छेद 131
III. अनुच्छेद 32
IV. अनुच्छेद 143

सही कूट का चयन करें:

- A) a-III, b-I, c-IV, d-II
B) a-II, b-I, c-IV, d-III
C) a-IV, b-III, c-II, d-I
D) a-I, b-II, c-III, d-IV

प्रश्न 59:

A) न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का मुख्य आधार संविधान का अनुच्छेद 13 है, जो मूल अधिकारों से असंगत विधियों को शून्य घोषित करता है।

B) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम 5

वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करना अनिवार्य है।

C) न्यायिक सक्रियता कभी-कभी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच 'शक्ति के पृथक्करण' के सिद्धांत को लेकर विवाद उत्पन्न कर देती है।

D) जनहित याचिका के तहत न्यायालय औपचारिक कानूनी प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए पत्र या पोस्टकार्ड को भी याचिका के रूप में स्वीकार कर सकता है।

प्रश्न 60:

भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) का दर्जा प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि इसके सभी निर्णय और आदेश न्यायिक साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं और उन पर देश के किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। साथ ही, इसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी प्राप्त है।

इस प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से सर्वाधिक उपयुक्त है?

A) अभिलेख न्यायालय होने के कारण उच्चतम न्यायालय को अपने फैसलों की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है।

B) इस शक्ति के तहत उच्चतम न्यायालय अपनी अवमानना करने वाले किसी भी व्यक्ति को केवल कारावास दे सकता है, आर्थिक दंड नहीं।

C) उच्चतम न्यायालय के निर्णय देश के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए पूर्व दृष्टांत (Precedents) के रूप में बाध्यकारी होते हैं।

D) यह शक्ति केवल उच्च न्यायालयों के पास होती है, उच्चतम न्यायालय के पास नहीं।

[प्रश्न अनुभाग 61 से 80]

प्रश्न 61:

कथन I : भारत निर्वाचन आयोग की मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया वही होती है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की होती है।

कथन II: अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की संस्तुति के बिना राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है।

कथन III : निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय निकाय है जो संसद, राज्य विधानमंडलों और

राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति के पदों के साथ-साथ राज्यों की पंचायतों के चुनावों का भी अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है।

उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन/कथन समूह सत्य है :

A) केवल 1

B) केवल 1 और 2

C) केवल 2 और 3

D) केवल 1 और 3

प्रश्न 62:

कारण: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) को भारत सरकार की संचित निधि से होने वाले सभी खर्चों की लेखापरीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु उसे राज्यों की संचित निधि की लेखापरीक्षा का अधिकार नहीं है।

कारण: सीएजी की रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करने के बाद सार्वजनिक लेखा समिति द्वारा उसकी गहन जांच की जाती है, जिससे कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित होता है।

A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है

B) A और R दोनों सत्य हैं परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है

C) A सत्य है, किन्तु R असत्य है

D) A असत्य है, किन्तु R सत्य है

प्रश्न 63:

नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, जिसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है।

निष्कर्ष I : नीति आयोग की शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक शामिल होते हैं।

निष्कर्ष II : नीति आयोग को राज्यों के लिए वित्तीय आवंटन करने और पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित करने की वैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं?

A) केवल निष्कर्ष I सत्य है

B) केवल निष्कर्ष II सत्य है

- C) निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं
D) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं

प्रश्न 64:

सूची I (आयोग/संस्थान):

- a) केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)
b) नीति आयोग (NITI Aayog)
c) भारत निर्वाचन आयोग (ECI)
d) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG)

सूची II (गठन वर्ष / अधिनियम):

- I. वर्ष 1950 (अनुच्छेद 324)
II. वर्ष 2003 (सांविधिक अधिनियम)
III. वर्ष 1858 (संवैधानिक प्रावधान के रूप में विकास)
IV. वर्ष 2015 (कार्यकारी संकल्प)

सही कूट का चयन करें:

- A) a-II, b-IV, c-I, d-III
B) a-I, b-II, c-III, d-IV
C) a-IV, b-III, c-II, d-I
D) a-III, b-I, c-IV, d-II

प्रश्न 65:

- A) लोकपाल संस्था में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 अन्य सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 50% सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए।
B) लोकपाल के चयन के लिए गठित चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और एक प्रख्यात न्यायविद शामिल होते हैं।
C) केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संधानम समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1964 में की गई थी, जिसे 2003 में वैधानिक दर्जा दिया गया।
D) लोकायुक्त की संस्था की स्थापना सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य द्वारा वर्ष 1971 में प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा पर की गई थी।

प्रश्न 66:

नीति आयोग ने भारत में पारंपरिक 'आदेश और नियंत्रण' वाली योजना प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है और इसके स्थान पर 'सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद' की नई संस्कृति को जन्म दिया है। यह देश के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करने के बजाय दीर्घकालिक, मध्यमकालिक और

अल्पकालिक रणनीतिक और विज्ञान दस्तावेजों को तैयार करने पर जोर देता है।

उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में नीति आयोग की कार्यपद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक तार्किक है?

- A) नीति आयोग राज्यों को राष्ट्रीय विकास एजेंडे पर एक साथ लाने के लिए 'टीम इंडिया हब' के रूप में कार्य करता है।
B) नीति आयोग के पास राज्यों की वार्षिक योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में धन आवंटित करने की अंतिम वित्तीय शक्ति है।
C) नीति आयोग की शासी परिषद की बैठकों की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
D) नीति आयोग के सभी सदस्यों का चयन सीधे जनता द्वारा लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।

प्रश्न 67:

संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) को भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख माना जाता है।

- A) सीएजी अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य सरकारी पद को ग्रहण करने के लिए पात्र नहीं होता है।
B) सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक होता है।
C) सीएजी को हटाने की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से होती है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है।
D) सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीधे अपने स्वविवेक से की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है।

प्रश्न 68:

कथन I : केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं।

कथन II: केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च स्तरीय

समिति की सिफारिश पर पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए की जाती है।

कथन III : लोकपाल अधिनियम 2013 के पारित होने के बाद भ्रष्टाचार के मामलों में केंद्रीय सतर्कता आयोग का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो गया है।

उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन/कथन समूह सत्य है :

- A) केवल 1 और 2
- B) केवल 2 और 3
- C) केवल 1 और 3
- D) केवल 1

प्रश्न 69:

कारण: भारत निर्वाचन आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है, किंतु लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने की शक्ति केवल परिसीमन आयोग के पास होती है।

कारण: निर्वाचन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण का कार्य सीधे अपने हाथ में ले सकता है यदि संसद उसे विशेष कानून बनाकर अधिकृत करे।

- A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है
- B) A और R दोनों सत्य हैं परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है
- C) A सत्य है, किन्तु R असत्य है
- D) A असत्य है, किन्तु R सत्य है

प्रश्न 70:

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने देश में भ्रष्टाचार विरोधी संस्थागत ढांचे को मजबूत किया है, जिसके तहत केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

निष्कर्ष I : लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य और समूह 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' के केंद्रीय सरकारी कर्मचारी शामिल होते हैं, हालांकि कुछ विशिष्ट शर्तों के साथ प्रधानमंत्री भी इसके दायरे में आते हैं।

निष्कर्ष II : लोकायुक्त की स्थापना करना सभी राज्यों के लिए पूरी तरह स्वैच्छिक है और केंद्र सरकार के अधिनियम के बाद किसी भी राज्य ने

अभी तक लोकायुक्त अधिनियम पारित नहीं किया है।

उपरोक्त में से कौन सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं?

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
- B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
- C) निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं
- D) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं

प्रश्न 71:

सूची I (संस्था/आयोग):

- a) भारत निर्वाचन आयोग
- b) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
- c) केंद्रीय सतर्कता आयोग
- d) लोकपाल

सूची II (संवैधानिक अनुच्छेद / अधिनियम वर्ष):

- I. वर्ष 2013 का अधिनियम
- II. अनुच्छेद 324
- III. वर्ष 2003 का अधिनियम
- IV. अनुच्छेद 148

सही कूट का चयन करें:

- A) a-II, b-IV, c-III, d-I
- B) a-IV, b-II, c-I, d-III
- C) a-III, b-I, c-IV, d-II
- D) a-I, b-III, c-II, d-IV

प्रश्न 72:

- A) भारत निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल संविधान में निश्चित रूप से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु निर्धारित किया गया है।
- B) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और वह लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।
- C) नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और सहकारी संघवाद को बढ़ाना है।
- D) लोकायुक्त संस्था की स्थापना सबसे पहले प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70) की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।

प्रश्न 73:

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार निवारण के लिए शीर्ष सतर्कता संस्था है। यह किसी भी मंत्रालय के सतर्कता प्रशासन पर नियंत्रण रखती है।

इस संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?

- A) सीवीसी की स्थापना वर्ष 1964 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर की गई थी।
- B) सीवीसी के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की समिति की संस्तुति पर की जाती है।
- C) सीवीसी अधिनियम 2003 के तहत इसे एक वैधानिक (Statutory) निकाय का दर्जा दिया गया है।
- D) सीवीसी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की सीधी जांच स्वयं अपने जासूसों से कराती है, सीबीआई की कोई भूमिका नहीं होती।

प्रश्न 74:

लोकपाल संस्था के चयन में पारदर्शिता और उच्च नैतिक मानकों को सुनिश्चित करने के लिए बहु-स्तरीय चयन समिति का प्रावधान किया गया है।

इस चयन समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?

- A) चयन समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता इसके सदस्य होते हैं।
- B) चयन समिति का गठन केवल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से ही किया जा सकता है।
- C) इस समिति में राज्यों के मुख्यमंत्रियों का होना अनिवार्य है।
- D) चयन समिति के सभी सदस्यों का चयन राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से करते हैं।

प्रश्न 75:

कथन I : नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) भारत के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है और वह केंद्र सरकार के खातों से संबंधित अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है।

कथन II: सीएजी राज्यों के खातों से संबंधित अपनी रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है ताकि उस पर चर्चा हो सके।

कथन III : नीति आयोग एक संविधिक निकाय है जिसे संसद के विशेष अधिनियम द्वारा वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं।

उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन/कथन समूह सत्य है :

- A) केवल 1
- B) केवल 1 और 2
- C) केवल 2 और 3
- D) केवल 1 और 3

प्रश्न 76:

कारण: भारत निर्वाचन आयोग के पास अपनी खुद की स्थायी प्रशासनिक और क्षेत्रीय मशीनरी नहीं होती है, बल्कि वह चुनाव के दौरान राज्यों के प्रशासनिक कर्मचारियों की सहायता पर निर्भर रहता है।

कारण: निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास बिना किसी संसदीय प्रक्रिया के होता है।

- A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है
- B) A और R दोनों सत्य हैं परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है
- C) A सत्य है, किन्तु R असत्य है
- D) A असत्य है, किन्तु R सत्य है

प्रश्न 77:

भारत में लोक वित्त के प्रबंधन और नियंत्रण में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसे डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बताया था।

निष्कर्ष I : सीएजी केवल पोस्ट-मॉर्टम लेखापरीक्षा (Post-mortem audit) करता है, अर्थात धन खर्च होने के बाद उसकी जांच करता है, खर्च होने से पहले नियंत्रण नहीं रखता।

निष्कर्ष II : सीएजी को देश के सार्वजनिक निगमों और कंपनियों की लेखापरीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है, यह कार्य केवल निजी ऑडिट फर्मों द्वारा किया जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं?

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
- B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
- C) निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं
- D) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं

प्रश्न 78:

सूची I (आयोग/संस्था के पदाधिकारी):

- a) मुख्य चुनाव आयुक्त
- b) केंद्रीय सतर्कता आयुक्त
- c) लोकपाल अध्यक्ष
- d) नीति आयोग के उपाध्यक्ष

सूची II (नियुक्ति/पद की प्रकृति):

- I. राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुति पर
- II. राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, उच्चतम न्यायालय के मानदंडों के अनुरूप
- III. प्रधानमंत्री द्वारा नामित एवं नियुक्त
- IV. राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, संसद के प्रस्ताव के बिना हटाये जाने वाले

सही कूट का चयन करें:

- A) a-IV, b-I, c-II, d-III
- B) a-II, b-IV, c-III, d-I
- C) a-I, b-II, c-IV, d-III
- D) a-III, b-I, c-II, d-IV

प्रश्न 79:

- A) नीति आयोग का शासी परिषद देश की विकास प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर विचार-विमर्श करने वाला प्रमुख मंच है।
- B) केंद्रीय सतर्कता आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं जब वह किसी मामले की प्रारंभिक जांच कर रहा होता है।
- C) भारत निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय के रूप में वर्ष 1950 से ही निरंतर कार्य कर रहा है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
- D) लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक होता है।

प्रश्न 80:

लोकपाल अधिनियम 2013 के अंतर्गत लोकपाल संस्था को भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच और अन्वेषण के लिए व्यापक अधिकार दिए गए हैं। इसके दायरे में लोक सेवक आते हैं, जिनमें अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी भी शामिल हैं।

इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से सर्वाधिक उपयुक्त है?

- A) लोकपाल सीधे तौर पर अपने अधीन किसी भी केंद्रीय एजेंसी (जैसे सीबीआई) को प्रारंभिक जांच या अन्वेषण का निर्देश दे सकता है।
 - B) लोकपाल के पास यह शक्ति है कि वह देश के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को सीधे पद से बर्खास्त कर सके।
 - C) लोकपाल का फैसला अंतिम होता है और इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती।
 - D) लोकपाल केवल कॉर्पोरेट घरानों के निजी वित्तीय घोटालों की जांच करने के लिए अधिकृत है, सरकारी अधिकारियों की नहीं।
- [प्रश्न अनुभाग 81 से 100]

प्रश्न 81:

कथन I : केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया था।

कथन II: मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।

कथन III : सूचना आयोग के सदस्यों का कार्यकाल मूल अधिनियम के अनुसार 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक निर्धारित किया गया था, जिसे 2019 के संशोधन अधिनियम द्वारा परिवर्तित कर दिया गया है।

उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन/कथन समूह सत्य है :

- A) केवल 1
- B) केवल 2 और 3
- C) केवल 1 और 3
- D) केवल 1 और 2

प्रश्न 82:

कथन: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष के रूप में केवल उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो।

कारण: मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत आयोग के अध्यक्ष और

सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है, और उन्हें पुनर्नियुक्ति का पात्र भी बनाया गया है।

- A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है
B) A और R दोनों सत्य हैं परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है
C) A सत्य है, किन्तु R असत्य है
D) A असत्य है, किन्तु R सत्य है

प्रश्न 83:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत को 'राज्यों का संघ' (Union of States) कहा गया है, जो इस बात को रेखांकित करता है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है।

निष्कर्ष I : भारतीय संघ से किसी भी राज्य को अलग होने का कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि यह एक अविभाज्य राज्यों का विनाशी संघ है।

निष्कर्ष II : प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्री के.सी. व्हीयर ने भारतीय संघीय व्यवस्था को 'अर्द्ध-संघीय' (Quasi-Federal) करार दिया है क्योंकि इसमें एकात्मक और संघीय विशेषताओं का अनूठा मिश्रण है।

उपरोक्त में से कौन सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं?

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
C) निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं
D) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं

प्रश्न 84:

सूची I (संविधान के अनुच्छेद/प्रावधान):

- a) अनुच्छेद 262
b) अनुच्छेद 263
c) अनुच्छेद 245
d) अनुच्छेद 249

सूची II (संबंधित प्रावधान/क्षेत्र):

- I. संसद की विधायी शक्तियों का क्षेत्रीय विस्तार
II. अंतर-राज्यीय जल विवादों का न्यायनिर्णयन
III. अंतर-राज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान
IV. राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति

सही कूट का चयन करें:

- A) a-II, b-III, c-I, d-IV
B) a-IV, b-II, c-III, d-I
C) a-III, b-I, c-IV, d-II
D) a-I, b-IV, c-II, d-III

प्रश्न 85:

A) केंद्र-राज्य विधायी संबंधों के अंतर्गत संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को प्राथमिकता मिलती है यदि केंद्र और राज्य दोनों के कानून में गतिरोध हो।

B) अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत संसद को अंतर-राज्यीय नदियों के पानी के प्रयोग और नियंत्रण पर न्यायनिर्णयन का अधिकार दिया गया है।

C) प्रशासनिक संबंधों के तहत केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है ताकि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग केंद्र की कार्यकारी शक्ति के विरुद्ध न हो।

D) वित्तीय संबंधों के तहत करों का अधिरोपण और उनका संग्रहण संघ सूची के मामलों में मुख्य रूप से केंद्र सरकार के अधीन होता है।

प्रश्न 86:

वर्ष 1989 के पश्चात भारतीय राजनीति में एकल पार्टी के प्रभुत्व का युग समाप्त हुआ और गठबंधन सरकारों (Coalition Governments) का दौर आरंभ हुआ। इसने क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने का अवसर दिया, जिससे कई बार राजनीतिक अस्थिरता और सौदेबाजी की राजनीति जैसी चुनौतियां भी उत्पन्न हुईं।

उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में गठबंधन राजनीति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक तार्किक है?

- A) गठबंधन सरकारों के दौर में क्षेत्रीय दलों के उभार ने संघीय संतुलन को और अधिक क्षेत्रीय और सहभागी बनाया है।
B) गठबंधन सरकारों के गठन से केंद्र सरकार की नीतियां इतनी मजबूत हो जाती हैं कि राज्यों की स्वायत्तता पूरी तरह समाप्त हो जाती है।
C) गठबंधन राजनीति ने राष्ट्रीय दलों के वर्चस्व को इस हद तक बढ़ा दिया है कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका है।

D) राष्ट्रीय एकता परिषद (NIC) का गठन गठबंधन सरकारों के टूटने से रोकने के लिए एक संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया था।

प्रश्न 87:

कथन I : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा छह सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति की संस्तुति पर की जाती है।

कथन II: मानवाधिकार आयोग को किसी भी मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में दोषियों को सीधे कारावास या आर्थिक दंड देने की न्यायिक शक्ति प्राप्त होती है।

कथन III : मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार आयोग के सदस्यों में मानवाधिकारों से जुड़े ज्ञान रखने वाले विशेष विशेषज्ञों का होना अनिवार्य है।

उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन/कथन समूह सत्य है :

- A) केवल 1 और 3
- B) केवल 2 और 3
- C) केवल 1 और 2
- D) केवल 1

प्रश्न 88:

कथन: सरकारिया आयोग (1983) ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि राज्यपाल के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिए जो राज्य की राजनीति से तटस्थ हो और सक्रिय राजनीति में सीधे संलग्न न रहा हो।

कारण: राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है, जिससे केंद्र और राज्य के बीच राजनीतिक गतिरोध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।

- A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है
- B) A और R दोनों सत्य हैं परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है
- C) A सत्य है, किन्तु R असत्य है
- D) A असत्य है, किन्तु R सत्य है

प्रश्न 89:

क्षेत्रीय परिषदों (Zonal Councils) की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई थी ताकि देश के विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग और समन्वय को बढ़ावा दिया जा सके।

निष्कर्ष I : क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय हैं जिनका स्पष्ट उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है।

निष्कर्ष II : देश में कुल पांच क्षेत्रीय परिषदें हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री इन सभी परिषदों के पदेन अध्यक्ष होते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं?

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
- B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
- C) निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं
- D) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं

प्रश्न 90:

सूची I (आयोग / समिति):

- a) सरकारिया आयोग
- b) पुंछी आयोग
- c) प्रशासनिक सुधार आयोग
- d) राष्ट्रीय एकता परिषद

सूची II (गठन वर्ष / स्थापना काल):

- I. वर्ष 2007
- II. वर्ष 1983
- III. वर्ष 1961
- IV. वर्ष 1966

सही कूट का चयन करें:

- A) a-II, b-I, c-IV, d-III
- B) a-I, b-II, c-III, d-IV
- C) a-IV, b-III, c-II, d-I
- D) a-III, b-IV, c-I, d-II

प्रश्न 91:

A) केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 2019 के संशोधन के बाद केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन कर दिया गया है।

B) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में भारत के केवल सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही नियुक्त हो सकते हैं (संशोधन के बाद अन्य न्यायाधीश भी पात्र किए गए हैं)।

C) अंतर-राज्य परिषद की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र-राज्य और अंतर-राज्य विवादों की जांच और सलाह के लिए की जाती है।
D) मदन मोहन पुंछी आयोग (2007) का संबंध मुख्य रूप से चुनाव सुधारों और निर्वाचन आयोग की शक्तियों की समीक्षा से था।

प्रश्न 92:

भारतीय संघवाद की वित्तीय व्यवस्था में राज्यों को वित्तीय रूप से स्वायत्त बनाने और करों के वितरण के लिए संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है।

इस वित्तीय संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?

- A) संसद को यह अधिकार है कि वह अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य पर कर लगाने के लिए कानून बना सकती है।
- B) कुछ कर ऐसे होते हैं जो केंद्र द्वारा लगाए और संग्रहित किए जाते हैं, किंतु उनका पूर्ण शुद्ध आगम राज्यों को सौंप दिया जाता है।
- C) संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में कर लगाने के विषय शामिल किए गए हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों समान रूप से कर वसूलते हैं।
- D) आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण संबंधी संवैधानिक प्रावधानों में फेरबदल कर सके।

प्रश्न 93:

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं।

जब कोई लोक सूचना अधिकारी (PIO) किसी नागरिक को समय पर सूचना नहीं देता या दुर्भावनापूर्ण तरीके से मना करता है, तो सूचना आयोग के पास क्या शक्ति होती है?

- A) आयोग दोषी अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश के साथ-साथ आर्थिक दंड (पेनल्टी) भी लगा सकता है।
- B) आयोग दोषी अधिकारी को सीधे जेल भेजने और उसकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे सकता है।
- C) आयोग के पास केवल मौखिक चेतावनी देने की शक्ति है, वह कोई आर्थिक दंड नहीं लगा सकता।
- D) आयोग केवल मामले को सीधे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है।

प्रश्न 94:

कथन I : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है, जिसे केंद्र सरकार संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाती है।

कथन II: यदि मानवाधिकारों के हनन का कोई मामला राज्य सूची के किसी विषय से जुड़ा है, तो मानवाधिकार आयोग उस पर सीधे जांच करने का कोई अधिकार नहीं रखता है।

कथन III : भारत में मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में जिला स्तर पर किया गया है।

उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन/कथन समूह सत्य है :

- A) केवल 1 और 3
- B) केवल 2 और 3
- C) केवल 1 और 2
- D) केवल 1

प्रश्न 95:

कारण: मदन मोहन पुंछी आयोग (2007) ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि राज्यपालों की नियुक्ति में राज्यों के मुख्यमंत्रियों से परामर्श लेने की परंपरा को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

कारण: राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं, इसलिए उनकी भूमिका को अधिक राजनीतिक और पक्षपातपूर्ण बनाया जाना चाहिए ताकि केंद्र के निर्देश आसानी से लागू हो सकें।

- A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है
- B) A और R दोनों सत्य हैं परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है
- C) A सत्य है, किन्तु R असत्य है
- D) A असत्य है, किन्तु R सत्य है

प्रश्न 96:

केंद्र-राज्य विधायी संबंधों में संविधान की सातवीं अनुसूची तीन सूचियों (संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची) का प्रावधान करती है, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के बीच विधायी क्षेत्रों का स्पष्ट विभाजन किया गया है।

निष्कर्ष I : यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद का कानून और राज्य का कानून दोनों मौजूद हों और उनमें टकराव हो, तो संसद का कानून मान्य होगा, बशर्ते राज्य के कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिली हो।

निष्कर्ष II : राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, किंतु आपातकाल समाप्त होने के छह महीने बाद वे कानून स्वतः समाप्त हो जाते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं?

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
- B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
- C) निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं
- D) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं

प्रश्न 97:

सूची I (निकाय / परिषद):

- a) अंतर-राज्य परिषद
- b) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
- c) केंद्रीय सूचना आयोग
- d) राष्ट्रीय एकता परिषद

सूची II (संविधान अनुच्छेद / प्रकृति):

- I. संविधिक (Statutory) निकाय
- II. संवैधानिक (Constitutional) निकाय - अनुच्छेद 263
- III. संविधिक निकाय - सूचना का अधिकार अधिनियम
- IV. गैर-संवैधानिक एवं गैर-संविधिक (विशाल राजनीतिक मंच)

सही कूट का चयन करें:

- A) a-II, b-I, c-III, d-IV
- B) a-IV, b-III, c-II, d-I
- C) a-I, b-II, c-IV, d-III
- D) a-III, b-IV, c-I, d-II

प्रश्न 98:

- A) भारत के संघीय ढांचे में समवर्ती सूची की अवधारणा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।
- B) अंतर-राज्यीय जल विवादों के समाधान के लिए बनाए गए न्यायाधिकरण (Tribunals) के फैसलों के विरुद्ध देश के किसी भी न्यायालय (उच्चतम

न्यायालय सहित) में अपील करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है।

C) क्षेत्रीय परिषदों का मुख्य उद्देश्य राज्यों के बीच क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को मजबूत करना है।

D) राष्ट्रीय एकता परिषद (NIC) की बैठकों की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

प्रश्न 99:

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक प्रमुख वैधानिक संस्था है। इसकी कार्यपद्धति में मानवाधिकार उल्लिखित मामलों की जांच और मानवाधिकार संस्कृति का प्रसार शामिल है।

इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से सर्वाधिक उपयुक्त है?

- A) मानवाधिकार आयोग किसी भी मामले में अपनी जांच शुरू करने के लिए घटना के एक वर्ष बाद भी स्वतंत्र रूप से संज्ञान ले सकता है।
- B) आयोग अपनी जांच के दौरान केंद्र या राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है और यदि सरकार कार्रवाई न करे तो वह सीधे राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश भेज सकता है।
- C) आयोग के पास किसी भी दोषी पुलिस अधिकारी को तुरंत बर्खास्त करने की दंडात्मक कार्यकारी शक्ति होती है।
- D) आयोग केवल विदेशी नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है, भारतीय नागरिकों के लिए नहीं।

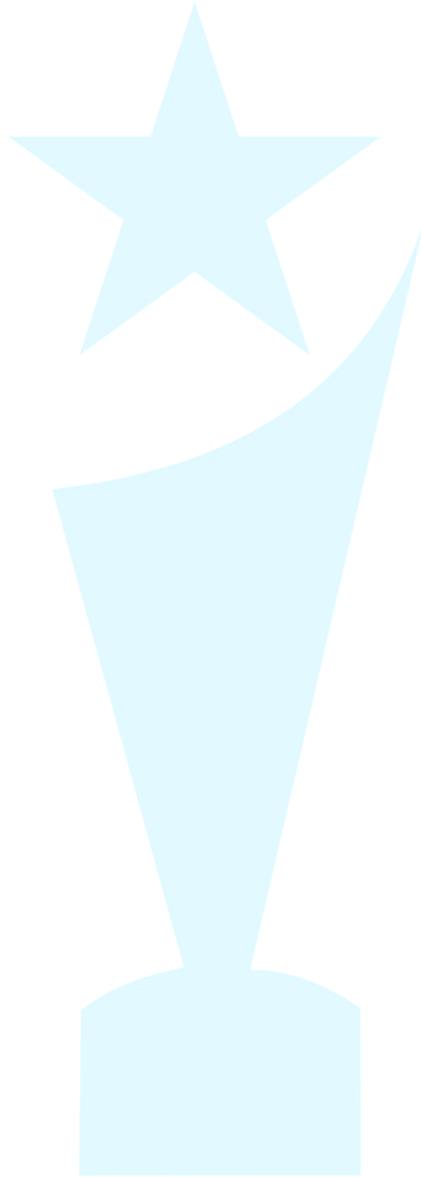
प्रश्न 100:

संघवाद की प्रकृति और केंद्र-राज्य संबंधों के विकास में विभिन्न आयोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकारिया आयोग (1983) और पुंछी आयोग (2007) ने भारतीय संघ को मजबूत करने के लिए विकेंद्रीकरण और राज्यपालों की भूमिका पर कई अहम सुझाव दिए हैं।

इस वैचारिक पृष्ठभूमि के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से सबसे सही है?

- A) दोनों आयोगों ने एक स्वर में यह स्वीकार किया कि राज्यपाल के पद को समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि यह संघीय भावना के विरुद्ध है।
- B) दोनों आयोगों ने अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के प्रयोग को अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल करने और इसके दुरुपयोग को रोकने की वकालत की है।

- C) सरकारिया आयोग ने राज्यों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता देने से स्पष्ट इनकार कर दिया था, जबकि पुंछी आयोग ने इसका पूरी तरह समर्थन किया।
D) दोनों आयोगों का मुख्य उद्देश्य देश में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था को और अधिक सरल और तीव्र बनाना था ताकि केंद्र मजबूत हो सके।



wincompete